ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **05 Sep, 2020**

Shri Rajeev Shukla, former Union Minister addressed media persons via video conferencing today.

श्री राजीव शुक्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपका एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने कल एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में आगे कोई भी नया सरकारी पद बनाने पर रोक लगा दी है, मौजूदा जो खाली पद हैं, उनको भरने पर रोक लगा दी है और इसके अलावा सलाहकार नियुक्त करने पर रोक है तथा किसी भी किस्म का रोजगार लोगों को देने पर एक प्रकार से रोक लगा दी है। ये सर्कुलर आपके सामने है, जो भारत सरकार ने जारी किया है, तो इसको आप देख लें, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है।

आज देश की आर्थिक हालत बहुत ही बुरी है। 45 साल में पहली बार जीडीपी में इतनी गिरावट आई है। इसे मैं आर्थिक संकट कहूंगा, घनघोर आर्थिक संकट है, इससे उबरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़कर आना चाहिए था, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं, जहाँ लॉकडाउन लागू हुआ है कि वो हर तरह से रोजगार बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोगों की प्राईवेट कंपनियों तक में सरकार तनख्वाह भेज रही हैं ताकि लोगों को तनख्वाह दी जा सके और उनको नौकरी से ना निकाला जा सके। यहाँ हालत ये है कि प्राईवेट सेक्टर में तो छंटनी चल रही है, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है, हर तरफ से उनकी हालत खराब हो रही है। अब सरकार ने भी अपनी नौकरियों पर रोक लगा दी है, तो इस तरह से युवा जाएगा कहाँ? ढाई प्रतिशत की दर से इस देश का युवा बढ़ रहा है हर साल, इन्हें कहाँ नौकरियां मिलेंगी, लोगों को कहाँ नौकरियां मिलेंगी? CMIE के डेटा से पता चला है कि किस तरह से 15 से 29 साल के लोगों के बीच में 17.8 प्रतिशत नौकरियां चली गई, बेरोजगारी आ गई और इसके अलावा 20 अगस्त तक 1.89 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, कहाँ 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया गया था हर साल, 2014 के चुनाव से पहले। 2 करोड़ नौकरी देना तो दूर, अब मेरे ख्याल से 2 करोड़ नौकरियाँ जा रही है हर साल। ये नया रिकोर्ड ये सरकार कायम कर रही है कि बजाए इसके कि 2 करोड नौकरी हर साल देने के, जो वायदा किया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों की जा रही है। त्राही-त्राही मची हुई है। प्राईवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, हर तरफ बुरा हाल है। इस हालत में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार ने ऐसा सर्कुलर क्यों जारी किया है कि जिसमें जो सारी किसी भी किस्म की पोस्ट, सरकारी पोस्ट क्रियेट करने पर मना कर दिया है, सरकारी विभागों को और जो मौजूदा खाली पोस्ट हैं, उनको भरने के लिए मना कर दिया है, तो ये कैसे चलेगा? ये सरकारी नौकरी ठप करने का जो सरकार का आदेश है, उस पर कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उसको तत्काल वापस लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी चाहिएं।

अभी आपको एक बात याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने एक भाषण में, यूथ को आश्वासन दिया था कि 2 लाख नौकरियां रेलवे में और एसएससी में दी जाएंगी और आप भी देखिए कि वो नौकरी तो छोड़ दी, उसकी जगह प्रधानमंत्री की घोषणा तो झूठी साबित हुई। वो कहते हैं कि किसी किस्म की नौकरी लोगों को मिलेगी नहीं, तो ये बेहद चिंता का विषय है। जो सरकार का नया फरमान है, नया आदेश है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, सरकार को रोजगार के नए पद और सृजन करने चाहिए बजाए इसके कि इन पर रोक लगाए, क्योंकि अगर सरकार आगे बढ़कर खर्च नहीं करेगी, तो ये इकोनॉमी निकल नहीं पाएगी और नीचे डूबती चली जाएगी। ये जो माईनस 23.9 प्रतिशत पर जीडीपी आई है, ये और नीचे चली जाएगी। तो इसलिए बहुत जरुरी है, हम मांग करते हैं कि सरकार ने ये जो प्रतिबंध लगाया है, इसको रोके और पद सृजन करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दे। दूसरे क्षेत्रों में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका बहुत बुरा हाल है, उन सेक्टर को मदद करे, वहाँ नौकरियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाएं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 12-13 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है। जब सरकार ही मान रही है कि इतनी नौकरियां चली गई हैं और ILO का डेटा है कि 48 लाख डेली वेजिस जो हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, 48 लाख, उनका काम चला गया। मेरे ख्याल से संख्या और भी ज्यादा है, 48 लाख नहीं, 68 लाख है, 68 लाख तो CMIE के डेटा में कहा गया है कि 68 लाख है, अगर आप ILO की रिपोर्ट देखें तो उनके हिसाब से 40 करोड़ लोग भारत में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले हैं।

मैं देश का योजना मंत्री था, मुझे याद है, मैंने पार्लियामेंट में भी वो डेटा बोला था कि ये पहली बार है 2005 से 2014 तक और 15 तक, करीब 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी की रेखा से निकाल कर बाहर लाए थे, ऊपर लेकर आए थे, जिसमें मनरेगा की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये संसद में हमारा बयान भी है और इसके अलावा उस समय के आंकड़े हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किए थे कि 2005 से 2015 के बीच में जो 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं भारत में। आज अब ILO क्या कह रहा है कि 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे भारत में चले गए हैं, ये तो किया कराया चौपट हो गया। जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया था, जितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए थे, वो सब नीचे चले गए और इसके अलावा सरकार पीछे हट रही है, बजाए कोई कदम बढ़ाने के, लोगों को रोजगार की व्यवस्था कराने के लिए, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राईवेट सेक्टर हो, सरकार लगातार पीछे हटती चली जा रही है।

उस समय डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ढाई प्रतिशत की दर से देश में यूथ बढ़ रहा है, इसलिए नौकरी का इंतजाम करना चाहिए, उस समय फिर योजना आयोग की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रपोजल आया था, वो स्किल डेवलपमेंट लागू किया था और फिर वो बढ़ता चला गया था। आज उस प्रोग्राम की क्या हालत है, पता नहीं, जगह - जगह उसमें भी शिकायतें आ रही हैं। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा, सरकारी दफ्तरों में ताला लगाने से काम नहीं चलेगा कि आप नौकरी नहीं देंगे। सरकार पीछे हट जाएगी, तो बहुत बड़ी समस्या देश में पैदा होने वाली है।

फिर इसी सर्कुलर में अगर आप देखें तो उन्होंने छोटी-छोटी चीजों पर रोक लगाई है, इतने कागज का इस्तेमाल मत करो, इतना फाउंडेशन दिवस अपने विभाग ना मनाएं। कोई कंसल्टेंट मत रखो, इन सब चीजों से ये छोटे-छोटे खर्चे बचाने से जो हजारों रुपए बचेंगे, एक फाउंडेशन डे पर किसी विभाग का कितना खर्च होगा, कुछ हजार खर्च होता है, 1 लाख खर्ज होगा। उससे नहीं होने वाला,

आज जो बेफिजूल के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको रिव्यू करिए, उनको रिव्यू करने से काम चलेगा। जो बेफिजूल के प्रोजेक्ट आपने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए घोषित किए हुए हैं, उनको रिव्यू करिए, उनको रोकिए, बजाए इसके कि कहीं आपने 10 हजार रुपए बचाए, कहीं 50 हजार बचा लिए, कहीं 1 लाख बचा लिए।

इसलिए जो सर्कुलर जारी हुआ है, ये बेहद मुझे लगता है कि जन विरोधी सर्कुलर है, कांग्रेस पार्टी इस सर्कुलर को तत्काल वापस लेने, नए रोजगार सृजन करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और इसके अलावा दूसरे सेक्टर के लिए सरकार को आगे बढ़कर मदद देने की अपील करती है। आज राहुल जी ने भी अपने ट्वीट में इस बात को स्पष्ट किया कि सरकार बजाए इसके कि लोगों को रोजगार दे, लोगों का रोजगार छीन रही है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि इस सर्कुलर को तत्काल वापस लिया जाए और जो खाली पद पड़े हैं सरकारी विभागों में, वो तत्काल भरे जाएं और इसके अलावा नए पद सृजित किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके।

Shri Rajeev Shukla said- Government of India has come out with the circular yesterday, which is dated 4 September, 2020, in which the creation of new jobs within the Government has been completely stopped. The Circular issued by the Finance Ministry suggested that new jobs cannot be created at all, the vacancies which are already existing should not be filled. This is a very alarming situation, since country's economy is already in doldrums. Our GDP has gone down -23.9%. ILO report suggests that 40 crores people are going to be below poverty line. So, in this situation, if Government stops helping people, if Government stops creating new jobs, if Government is not coming forward, or stepping up to support the young people, then who is going to support them?

Private sectors are already into retrenchment because their financial situation is very bad and the Government is not helping them as well in terms of loan waiver and all that and the Supreme Court is already hearing the matter. So, there is a retrenchment in Private Sector. Now, in public sector, if the Government is also not helping the people, so the Congress Party demands that more and more vacancies should be created, more and more posts should be created in the Government, all the vacancies which are already existing should be filled immediately and people should be provided employment and all those sectors should be helped where more and more employment opportunities can be created. This is the demand of the Congress Party.

Today, Shri Rahul Gandhi JI has already tweeted that how the employment from the people, how the jobs from the people are being taken away and Government is not helping them. So, we are further emphasizing on this issue that Government should create more jobs instead of banning the Jobs and the Government should re-consider this circular and apart from that the second part of the circular is suggesting that the Government expenditure in certain

areas should be curbed, but, there are very trivial, very frivolous items which have been shown into, like the use of papers, the celebrations of foundation day, there are various departments which are distributing bags and momentos, all should be banned. How much are you going to save about it? Few thousands, few lakhs, that is not going to make any difference, actually the Government should reconsider all those projects, Government's projects by which you are trying to derive publicity and you have been spending thousands and thousands crores on those projects, those projects for the time being should be stopped. If your economy is not able to bear the burden of that kind of projects, you should stop them temporarily and after a while, when your economy improves, then you can definitely go for those projects, but, not for now.

So, we are demanding that the job opportunities should be increased, enhanced and secondly you know that all these big projects should be put on hold, those which are not required immediately, the emergency projects, all those projects which has got sanctioned with necessary infrastructure, you should carry on. But all those projects, where you are going to derive the publicity, I think you should reconsider those projects and there is a data by CMIE which is also suggesting that between July, 2017 and June, 2018 in the age bracket of 15-29 years, there was 17.8% unemployment and which is increasing day by day and up to 20th August, 2020, 1.89 crore people have lost their jobs. In my view, if you calculate organized and unorganized sectors both, 12 crore people or 13 crore people have lost their jobs, but, the Government itself is confessing that around 2 crore people have lost their jobs. So, now, I would like to point out or I would like to remind you people that when BJP was contesting 2014 elections, promise had been made to the nation that every year we will give 2 crores employments, we will create 2 crores jobs, which will be given to the people. Here, the authentic data is showing that 2 crore people have lost jobs in few months. So, every year instead of creating 2 crore jobs, people are losing 2 crore jobs. So, this is a very-very alarming situation and we demand from the Government that in this moment of economic crisis, Government should step up its efforts. Government should come forward to help people instead of backing out, this is what I want to appeal to the Government through the Media friends.

एक प्रश्न पर कि आपने कहा कि सरकार को चाहिए कि पहले अपने बेफिजूल के प्रोजेक्टस रोके, तो क्या इशारा नए पार्लियामेंटरी बिल्डिंग की ओर भी है, जिसकी कांग्रेस बार-बार मांग करती रही है, श्री शुक्ला ने कहा कि एक प्रोजेक्ट की तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही मांग कर रही है, और भी तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो सरकार कर रही है, जिनमें हजारों, लाखों करोड़ लग रहे हैं, जैसे बुलेट ट्रेन वाला सुना है, रिव्यू कर रही है सरकार, तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किए गए थे, ताकि उनका नाम हो, तो उन चीजों पर विराम लगाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से लोगों को नौकरी देने का काम करना चाहिए, ऐसे सेक्टर्स की मदद करनी चाहिए, जहाँ

ज्यादा से ज्यादा नौकरियाँ दी जा सकती हैं, ताकि बेरोजगारी की संख्या, जो करोड़ों में बढ़ती जा रही है, उस पर काबू पाया जा सके।

एक अन्य प्रश्न पर कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जी ने मास्को समिट में बात की है चाइनीज़ काउंटरपार्ट से और साफ तौर पर कहा है कि भारत की सेनाएं अपने सोवर्निटी बचाने के लिए वहाँ खड़ी हैं, बातचीत से हल निकलना चाहिए और बातचीत लगातार जारी है, पर साफतौर से स्टेट्स को मेंटेन करने की बात कही गई है, लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि बातचीत जारी है, और जल्द ही इसका कोई हल निकलेगा, श्री शुक्ला ने कहा कि हम सब इसकी आशा करते हैं, कि इसका कोई हल निकले, बातचीत के जरिए कोई हल निकले, लेकिन आप लोग देखिए न कि उसी के साथ-साथ विदेश सचिव का बयान क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं कि 1962 से ज्यादा स्थिति खराब हुई है अब, भारत चीन सीमा पर भारी तनाव है। तो एक तरफ विदेश सचिव का स्टेटमेंट आ रहा है, एक तरफ राजनाथ सिंह जी चीन के रक्षामंत्री से बात करते हैं और कहते हैं कि हम समस्या का हल निकाल रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्थिति क्या है, सरकार को बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए, उस दिन भी हमने यहीं मांग रखी थी कि हमारी किन-किन जगहों पर चीनी सेना घुसी है, उसका सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अभी अरुणाचल प्रदेश में हमारे 5 भारतीय नागरिकों के अपहरण की बात आ रही है, वो भी एक खबर आई हुई है, तो ये चीनी सीमा पर स्थिति बहुत खराब है, जो विदेश सचिव ने आगाह किया है और ऐसे में भारत सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है, अगर बातचीत के जरिए रास्ता निकले तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम तो चाहते हैं कि बातचीत से इस समस्या का हल हो। श्री राजीव गांधी जी ने चीन के साथ एक डायलॉग शुरु किया था, श्री नरसिम्हा राव जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया था, फिर लगातार सरकारों ने उसको आगे बढ़ाया तो आज स्थिति इतनी क्यों बिगड़ी है, आज स्थिति ऐसी क्यों आ गई है, जबकि चीन के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के काफी वार्तालाप हुए, काफी उनको घुमाया फिराया सब जगह देश में, लेकिन इसके बावजूद स्थिति खराब हुई है, तो इस पर सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए। जो सरकार के अंदर ही परस्पर विरोधी बयान आते हैं, वो हमारी चिंता के सबसे बड़े कारण हैं।

एक अन्य प्रश्न पर कि राजनाथ सिंह जी ने चीन को साफतौर पर आगाह किया है कि जो एलएसी पर किया जा रहा है, जो वायलेशन किया जा रहा है, ये बाईलेटरल एग्रीमेंट का भी वायलेशन है, तो सीधे तौर पर बातचीत में ये भी हमारे रक्षामंत्री ने बात चीन के सामने रखी है, श्री शुक्ला ने कहा कि हाँ, तो इसका मतलब सबसे पहले तो रक्षामंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि वायलेशन हो रहा है। हमारी सीमा का वायलेशन हो रहा है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जो कि सरकार में दूसरे उच्च पदों पर रहते हुए मानने को तैयार नहीं थे, एक तो उन्होंने कहा कि वायलेशन हो रहा है, फिर ये मुद्दा उन्होंने उनके सामने रखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को कड़ाई से रखना चाहिए सरकार को, कांग्रेस पार्टी समझती है और किसी भी कीमत पर हमारी भूमि, हमारी जमीन के साथ समझौता नहीं हो सकता है और हमें कड़े शब्दों में उनको बताना चाहिए और उसके साथ-साथ बातचीत की भी प्रक्रिया सफल हो, ऐसी उम्मीद भी हम सरकार से करते हैं।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC